सैंसेक्स 22 अंक चढ़ा और निफ्टी 10820 के करीब बंद

नई दिल्ली, 15 जून (ए)। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में आज सैंसेक्स 22.32 अंक यानि 0.063 फीसदी बढ़कर 35,622.14 पर और निफ्टी 9.65 अंक यानि 0.089 फीसदी बढ़कर 10,817.70 पर बंद हुआ।
मिड-स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट: मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी गिरावट दिखी है। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.40 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.46 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी का मिडकैप 100 इंडेक्स 0.73 फीसदी तक गिरकर बंद हुआ है।
बैंक निफ्टी में गिरावट: फार्मा, आईटी में आज बढ़त देखने को मिली है। आईटी में 2.23 फीसदी, फार्मा शेयर में 2.24 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 0.55 फीसदी, ऑटो शेयर में 0.62 फीसदी, मेटल शेयरों 1.53 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

सोने में 330 रुपए का उछाल चांदी 42 हजार रुपए के पार

नई दिल्ली, 15 जून (ए)। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख तथा स्थानीय आभूषण विनिर्माताओं की खरीदारी से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना आज 330 रुपए की बढ़त के साथ 32,190 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। वहीं औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का विनिर्माताओं का उठाव बढ़ने से चांदी 450 रुपए की बढ़त के साथ 42,000 रुपए के स्तर को पार कर 42,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बाजार कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ने से वैश्विक बाजारों में डॉलर कमजोर हुआ है। इससे सोने में मजबूती आई है। इसके अलावा घरेलू हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण विनिर्माताओं की मांग बढ़ने से भी सोने में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर कल न्यूयॉर्क में सोना 0.24 प्रतिशत चढ़कर 1,301.90 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी भी 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17.13 डॉलर प्रति औंस रही।

डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर: विशेषज्ञों ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है जिससे पीली धातु का आयात महंगा हुआ है। इस वजह से भी सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 330-330 रुपए की बढ़त के साथ क्रमश = 32,190 रुपए और 32,040 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। कल के कारोबार में सोना 90 रुपए टूटा था। चांदी सिक्का लिवाल 76,000 रुपए और बिकवाल 77,000 रुपए प्रति सैकड़ा पर कायम रहा।

खादी के नाम पर फैब इंडिया का धोखा, हाई कोर्ट में किया 525 करोड़ रुपए का केस

नई दिल्ली 15 जून (ए)। खादी के कपड़े बेचने वाले ब्रैंड फैब इंडिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने कंपनी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया है। आयोग ने फैब इंडिया पर फैक्ट्री में बने सूती कपड़ों को खादी के नाम पर बेचने और उसे 525 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। खादी आयोग की तरफ से केस लड़ने वाली लॉ फर्म कोचर ऐंड कंपनी ने फैब इंडिया से कहा कि वह खादी ट्रेडमार्क के जरिए कपड़े बेचे जाने के चलते हुए नुकसान की भरपाई करे। फैब इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, इस संबंध में अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। इस संबंध में उससे पहले कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। देश में खादी के प्रोत्साहन का काम देखने वाली संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग का कहना है कि उसने फैब इंडिया को यह अधिकार नहीं दिए हैं कि वह खादी ब्रैंड के तहत कपड़े बेचे।

एप्पल आईफोन में सेंध लगाना होगा नामुमकिन

वाशिंगटन 15 जून (ए)। लग्जरी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने कहा कि वह बिना वैध अधिकार के हैंडसैट अनलॉक करने की पुलिस की कोशिशों को रोकने के लिए आईफोन का इनक्रिप्शन कठिन बना रही है। एप्पल ने यह कदम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जारी टकराव के बीच उठाया है। ऐसी खबरें हैं कि पुलिस आईफोन के सुरक्षा फीचरों को तोड़ने के लिए 'ग्रेकी' नामक समाधान का लगातार इस्तेमाल कर रही है। एप्पल ने कल कहा कि नए सुरक्षा फीचर सुरक्षा एजेंसियों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि अच्छे-बुरे दोनों तरह के लोगों को अवैध तरीके से इनक्रिप्शन में सेंध लगाने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। कंपनी ने जारी बयान में कहा, ''एप्पल में हम अपने हर डिजाइन के केंद्र में उपभोक्ताओं को रखते हैं।'' एप्पल ने कहा, ''हम एप्पल के हर उत्पाद में सुरक्षा संरक्षण को मजबूत बना रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को हैकरों, पहचान चोरों तथा निजी सूचनाओं में सेंध से बचाया जा सके।

कीटनाशक दवाओं के बाजार में विदेशी माल का दबदबा

नई दिल्ली 15 जून (ए)। कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के संगठन ने कीटनाशकों के लिए आयात पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताई है। उसका कहना है कि आयातित कीटनाशकों में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के पंजीकरण की आवश्यकता खत्म होने से देश में कीटनाशकों का आयात तेजी से बढ़ रहा है, घरेलू विनिर्माताओं के लिए समस्या उत्पन्न हुई है और किसानों को आयातित रसायन के लिए महंगा दाम चुकाना पड़ रहा है।

पैस्टीसाइड मैन्युफैक्चरर्स एंड फार्मूलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.एम.एफ.ए.आई.) के अध्यक्ष प्रदीप दवे ने कहा, ''यू.पी.ए. शासनकाल के दौरान वर्ष 2007 में कीटनाशकों में प्रयुक्त होने वाली दवाओं का विवरण (जिसे टैक्नीकल बोला जाता है) के सैंट्रल इंसैक्टेसाइड बोर्ड के साथ पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी और केवल

कीटनाशक दवा (फार्मूलेशन) का पंजीकरण करने की व्यवस्था को बरकरार रखा गया जहां से सारी समस्या उत्पन्न हुई है।'' दवे ने कहा, ''भारत में कीटनाशक क्षेत्र वर्ष 1968 के इंसैक्टेसाइड कानून' से संचालित होता है।''

भारतीय कंपनियों के लिए कीटनाशकों का उत्पादन करना मुश्किल: उन्होंने कहा, ''इस व्यवस्था के कारण भारतीय कंपनियों के लिए कीटनाशकों का उत्पादन करना मुश्किल हो गया है क्योंकि इसमें कीटनाशकों को तैयार करने के लिए लगभग 5-6 साल लगते हैं और भारी मात्रा में आंकड़ों को एकत्रित करना होता है साथ ही कंपनियों पर इस काम के लिए 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है जबकि विदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास ये आंकड़े तैयार होते हैं और उन्हें अपने 'टैक्नीकल' (कीटनाशक में प्रयुक्त होने वाली दवाओं) का पंजीकरण करवाने की अनिवार्यता नहीं रह गई है।

इसके अलावा उनके पास 20 साल तक का पेटैंट भी होता है जिस कारण दूसरी कंपनियों के लिए उसकी नकल पेश करने में कानूनी अड़चनें आती हैं।''

विदेशी कंपनियां कर रहीं अनाप-शनाप रसायनों का इस्तेमाल: उन्होंने कहा, ''इस स्थिति में विदेशों से आयात होने वाले कीटनाशकों और उसमें प्रयुक्त अवयवों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी कंपनियां अनाप-शनाप रसायनों का इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि अब उन्हें 'टैक्नीकल' का पंजीकरण नहीं करवाना होता है। इसके कारण किसानों को कम उपज मिल रही है लेकिन फिर भी अपनी फसलों की रक्षा के लिए वे महंगे दामों पर विदेशी कीटनाशकों को खरीदने के लिए विवश हैं।''

इसके उलट भारतीय कंपनियों के लिए अपनी कीटनाशक दवा (फार्मूलेशन) के साथ 'टैक्नीकल' (दवा में प्रयुक्त होने वाले रसायनों का विवरण) का पंजीकरण कराना अनिवार्य बना हुआ है।

FY17 में OLA को 4897 करोड़ का घाटा, इनकम 70 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली 15 जून (ए)। भारत की राइड हेलिंग ऐप ओला का वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान घाटा बढ़कर 4,897 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, हालांकि उसकी कुल इनकम में 70 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। रेग्युलेटरी डॉक्यूमेंट्स से ये आंकड़े सामने आए हैं। भारत में मार्केट लीडरशिप के लिए अमेरिकी कंपनी उबर से भारी कॉम्पिटिशन का सामना कर रही ओला को वित्त वर्ष 2015-16 में 3,147.9 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

70 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 1380.70 करोड़ रु की इनकम: इसी अवधि के दौरान ओला ब्रांड के तहत सेवाएं देने वाली एएनआई टेक्नोलॉजिज को कंसॉलिडेटेड कुल इनकम 70 फीसदी बढ़कर 1,380.70 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई, जबकि एक साल पहले (वित्त वर्ष 2015-16 में) यह आंकड़ा 810.70 करोड़ रुपए रहा था। इस संबंध में भेजे गए ई-मेल पर ओला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

1,000 करोड़ रु का हुआ एकमुश्त नुकसान: रिसर्च फर्म टॉफ्लर की को-फाउंडर अंचल अग्रवाल ने कहा, '1000 करोड़

रुपए के एकमुश्त नुकसान से कंपनी के नतीजों पर खासा निगेटिव असर पड़ा। ई-कॉमर्स कंपनियों के नतीजों की तर्ज पर कंपनी का एडवर्टाइजिंग खर्च 35 फीसदी कम हुआ है।' रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) में फाइल किए गए डॉक्यूमेंट के मुताबिक, ओला को वित्त वर्ष 2017 के दौरान 'मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट' के एवज में 1,095.3 करोड़ रुपए का एकमुश्त नुकसान हुआ।

2011 में शुरू हुई थी कंपनी: 2011 में भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी द्वारा स्थापित ओला 110 शहरों में सेवाएं देती है और कंपनी अपने साथ 10 लाख ड्राइवर-पार्टनर्स, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के जुड़े होने का दावा करती है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के बाजार में उतरने का ऐलान किया था और अब पर्थ, सिडनी व मेलबर्न सहित कई शहरों में सेवाएं देती है। यहां भी कंपनी को उबर से प्रतिस्पर्धा मिल रही है।

ब्रिटेन-आयरलैंड में कागज से बने स्ट्रॉ का इस्तेमाल करेगी मैकडोनाल्ड

नई दिल्ली 15 जून (ए)। फास्टफूड रेस्तरां चेन चलाने वाली कंपनी मैकडोनाल्ड ने आज कहा कि वह ब्रिटेन एवं आयरलैंड के अपने सभी आउटलेटों में कागज से बने स्ट्रॉ का इस्तेमाल करने वाली है। उसने कहा कि इस साल के अंत में अमेरिका में भी कुछ आउटलेटों में प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह कागज से बने स्ट्रॉ का परीक्षण करेगी।

प्लास्टिक स्ट्रॉ को बंद करने का दबाव: बर्गर तथा अन्य फास्टफूड चेन चलाने वाली कंपनियों को प्लास्टिक स्ट्रॉ के इस्तेमाल को लेकर उपभोक्ताओं तथा पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वे प्लास्टिक स्ट्रॉ के इस्तेमाल को बंद करने का दबाव बना रहे हैं क्योंकि ये अंततः समुद्र में पहुंचकर समुद्री कछुए, पक्षी तथा अन्य समुद्री जीवों की मौत का कारण बन रहे हैं। इसकी जगह कागज से बने स्ट्रॉ

विघटित हो जाते हैं। मैकडोनाल्ड ने हालांकि यह बताने से इंकार कर दिया कि वह अमेरिका में किस तरह के स्ट्रॉ का परीक्षण करने जा रही है। उसने बस इतना कहा कि वैकल्पिक स्ट्रॉ टिकाऊ समाधान होगा।

अमेरिका में 14 हजार रेस्तरां: मैकडोनाल्ड के अमेरिका में 14 हजार से अधिक तथा ब्रिटेन एवं आयरलैंड में करीब 1,360 रेस्तरां हैं। कंपनी ब्रिटेन एवं आयरलैंड में प्लास्टिक स्ट्रॉ को कागज से बने स्ट्रॉ से स्थानापन्न करने की शुरुआत करेगी और अगले साल तक इसे पूरा कर लेगी। कंपनी की योजना वैकल्पिक स्ट्रॉ का परीक्षण फ्रांस, स्वीडन एवं नॉर्वे के रेस्तरां में भी करने की है।

आईसीआईसीआई बैंक में हितों के टकराव की जांच करेंगे जस्टिस श्रीकृष्ण

मुंबई, 15 जून (ए)। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी एन श्रीकृष्ण आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर पर लगे आरोपों की जांच करेंगे। बैंक के बोर्ड ने जांच के लिए उनसे संपर्क किया था, जिस पर श्रीकृष्ण ने सहमति दे दी है। इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया, च्जस्टिस श्रीकृष्ण जाने-माने और भरोसेमंद नाम हैं। फाइनैंशल मार्केट्स की उन्हें बखूबी समझ है। बोर्ड को लगा कि वह इस जांच के लिए सबसे योग्य होंगे। इसके बाद उनसे इस बारे में बात की गई और वह इसके लिए तैयार हो गए।

जस्टिस श्रीकृष्ण इसकी जांच करेंगे कि क्या चंदा कोचर ने बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया

है और क्या बैंक के कुछ बॉरोअर्स को कर्ज देने के बदले उन्होंने उनसे कोई फायदा लिया है जस्टिस श्रीकृष्ण फाइनैंशल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन (स्नस्स्रष्ट) के चेयरमैन थे। वह अभी एक्सपर्ट्स की एक कमेटी के हेड हैं, जिसे देश में डेटा प्रटेक्शन फ्रेमवर्क पर सुझाव देने के लिए बनाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के मामले में जस्टिस श्रीकृष्ण ने कमेंट करने से मना कर दिया। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड ने इस जांच को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है। आईसीआईसीआई बैंक ने 30 मई को स्टॉक एक्सचेंजों को बताया था, च्व्यापक जांच की जाएगी। जांच के दौरान जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें बैंक मुहैया कराएगा। इस जांच से मसले का अंतिम नतीजा सामने आएगा।

क्या हैं आरोप : चंदा कोचर पर आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप के लिए जब 2012 में बैंक ने 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी थी, तब वह बैंक की क्रेडिट कमेटी में थीं। वहीं, वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की 2008 में प्रमोटेड न्यूपावर रिन्यूएबल्स में पहले निवेशक थे। धूत ने इसके बाद अपना स्टेक बेच दिया था, लेकिन उनके कंट्रोल वाली कंपनियों या सहयोगियों ने 2013 की शुरुआत तक न्यूपावर के साथ रिश्ते बनाए रखे थे। उसके बाद कंट्रोल दीपक कोचर को बहुत मामूली रकम में ट्रांसफर किया गया। बैंक और चंदा कोचर ने इस मामले में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। सेबी ने भी बैंक से वीडियोकॉन ग्रुप और न्यूपावर रिन्यूएबल्स को लेकर कथित आरोपों पर जवाब मांगा था। न्यूपावर रिन्यूएबल्स को चंदा कोचर के पति दीपक कोचर चलाते हैं।

इलाज में बड़ी छूट देने की तैयारी में सरकार मेडिकल डिवाइसेज को सस्ता करने की तैयारी

नई दिल्ली 15 जून (ए)। केंद्र की मोदी सरकार आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मेडिकल डिवाइसेज के दामों में कमी की सौगात आम जनता को दे सकती है। सरकार इन डिवाइसेज के ट्रेड मार्जिन को 30 पर्सेंट तक सीमित करने की तैयारी कर रही है। इससे डिस्ट्रिब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और अस्पतालों की ओर से मरीजों से अधिक वसूली किए जाने पर लगाम लग सकती है।

सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने यह सुझाव दिया है ताकि मेडिकल डिवाइसेज और सर्विसेज को अफोर्डेबल किया जा सकेगा। आयोग ने सुझाव दिया है कि इन डिवाइसेज के ट्रेड मार्जिन को तार्किक स्तर पर लाने को लेकर विचार करना चाहिए। इसी के तहत पहले पॉइंट ऑफ सेल पर इन डिवाइसेज को 30 फीसदी मार्जिन तक लाने का सुझाव है।

हाल ही में पीएमओ के साथ हुई मीटिंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नीति आयोग ने इस मसले को लेकर मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरर्स और पब्लिक हेल्थ ग्रुप्स के अलावा सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। नीति आयोग ने अफोर्डेबल मेडिसिन्स और हेल्थ प्रॉडक्ट्स की स्टैंडिंग कमिटी से कहा है कि उसे एक ऐसी मेडिकल डिवाइसेज की लिस्ट तैयार करनी चाहिए, जो जिससे मार्जिन को सीमित किया जा सके और अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके। फिलहाल भारत की ओर से 75 फीसदी मेडिकल डिवाइसेज का आयात होता है। यही नहीं इस आयात में से 80 फीसदी डिवाइसेज वे होती हैं, जिनका जटिल इलाज के लिए इस्तेमाल होता है और इनकी कीमत खासी अधिक है। फिलहाल देश में मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कार्डिएक स्टेंट, ड्रग इलुटिंग स्टेंट, कॉन्डम्स और इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज की कीमतें ही पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हैं। सरकार ने इन्हें जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर रखा है। इनके अलावा हाल ही में घुटनों के इलाज के लिए जरूरी डिवाइसेज को भी प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी के तहत लाया गया है। इनके अलावा बाकी डिवाइसेज पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पीएमओ के साथ हुई मीटिंग में साझा किए गए ऐक्शन प्लान के मुताबिक, यह सुझाव दिया कि दवाइयों, इलाज और जरूरी डिवाइसेज को कीमत नियंत्रण की नीति के तहत लाया जाना चाहिए। इससे सभी मेडिकल डिवाइसेज की कीमतें और अन्य हेल्थ प्रॉडक्ट्स के प्राइस नियंत्रण में रह सकेंगे।

ताज मानसिंह की नीलामी लटकी, अब फिर आएगी नई तारीख

नई दिल्ली 15 जून (ए)। ताज मानसिंह होटल की नीलामी के लिए नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) अगले एक महीने के भीतर नई तारीख जारी करेगी। इसके साथ ही एनडीएमसी पुराने टेंडर डॉक्युमेंट और उससे जुड़ी शर्तों में कोई बदलाव नहीं करेगी। एक अधिकारी ने बताया, नीलामी टेंडर के मुताबिक ही कराई जाएगी। टेंडर के नियमों के मुताबिक नीलामी की प्रक्रिया को कम से कम तीन बिडर्स के आने के बाद बढ़ाई जाएगी। हालांकि अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस नियम में ढील देते हुई 2 बिडर्स के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा किसी और नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। ताज मान सिंह होटल का संचालन अभी इंडियन होटल्स कंपनी (आईएचसीएल) के पास है। अभी तक आईएचसीएल इस होटल के लिए इकलौती बिडर्स के तौर पर सामने आई है।

दिवालिया हुई कंपनी को नहीं मिला खरीदार, लटकी कुर्की की तलवार

नई दिल्ली 15 जून (ए)। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही मोनेट इस्पात की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कंपनी के लिए बोली लगाने के आखिरी दिन भी कोई बोलीदाता आगे नहीं आया। जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार सरकार के ऐक्शन का इंतजार करने या डूब चुके लोन को किसी बैड बैंक के पास ट्रांसफर करने के विकल्प भी सामने हैं।

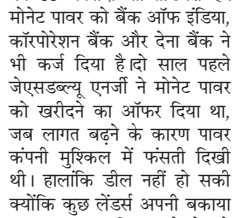

कई बैंकों को पड़ेगा घाटा: रिजॉलूशन प्रफेशनल ने 19 जून को क्रेडिटर्स की कमेटी की बैठक बुलाई है ताकि बोली का एक और राउंड आयोजित करने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा सके। मोनेट इस्पात को दिए कर्ज पर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। मोनेट पावर पर लेंडर्स के 7,652 करोड़ रुपए बकाया हैं। मोनेट पावर स्टील बनाने वाली कंपनी मोनेट इस्पात

की 88 फीसदी सब्सिडियरी है। मोनेट पावर को बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और देना बैंक ने भी कर्ज दिया है।दो साल पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने मोनेट पावर को खरीदने का ऑफर दिया था, जब लागत बढ़ने के कारण पावर कंपनी मुश्किल में फंसती दिखी थी। हालांकि डील नहीं हो सकी क्योंकि कुछ लेंडर्स अपनी बकाया रकम का कुछ हिस्सा छोड़ने को राजी नहीं थे। बता दें कि मोनेट अभी 10 लाख टन सालाना कैपेसिटी पर काम कर रही है, जबकि जेएसडब्ल्यू की योजना इसे बढ़ाकर कुछ साल में 25 लाख टन तक ले जाने की है।

पतंजलि का ऐलान, 2018 के अंत तक मार्केट में आ जाएगी स्वदेशी जींस

नई दिल्ली 15 जून (ए)। योग गुरु बाबा रामदेव की स्वदेशी कंपनी पतंजलि की जींस पहनने का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक, साल के अंत तक पतंजलि अपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी कपड़े का उद्योग शुरू कर देगी। इस बात की जानकारी पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में दी है। बता दें कि इस बात का ऐलान पहले ही चुका था कि

पतंजलि परिधान नाम से अपनी कपड़ों की ब्रैंड लॉन्च करेगी। अब इंटरव्यू के जरिए बालकृष्ण ने इस प्लान के बारे में और जानकारियां दी हैं। बालकृष्ण के मुताबिक, कपड़ा उद्योग का सारा काम नोएडा से संचालित होगा, जिसके लिए एक टीम पहले ही बनाई जा चुकी है। कपड़ों का निर्माण किसी थर्ड पार्टी से करवाया जाएगा। पतंजलि शुरुआत में परिधान के 100 एक्सक्लूसिव शोरूम खोलेगी।

शोरूम में क्या-क्या होगा

परिधान के बारे में योगगुरु रामदेव से भी पहले कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। उन्होंने बताया था कि परिधान में 3000 के करीब आइटम होंगे। जिसमें बच्चों के कपड़े, योगा की ड्रेस, स्पोर्ट्सवेअर, टोपी, जूते, तौलिया, बेडशीट्स मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिस्ट में है।

जींस होगी खास

पतंजलि के कपड़े के शोरूम खुलने से पहले ही उसकी जींस की चर्चा शुरू हो गई थी। जिसकी खूबियां बालकृष्ण ने तकरीबन दो साल पहले ही बता दी थी। उस वक्त यह प्रॉजेक्ट एक कॉन्सेप्ट ही था। बालकृष्ण ने तब बताया था कि महिलाओं के लिए उनकी जो जींस होंगी वे भारतीय कल्चर के हिसाब से होने के साथ-साथ ज्यादा आरामदायक भी होंगी। उन्होंने बताया था, जींस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। विदेशी चीजों के साथ हम दो चीज कर सकते हैं, या तो हम उनका बहिष्कार कर दें, या फिर अपने तरीके से अपना लें। अब जींस लोगों के बीच काफी प्रचलित है, ऐसे में उसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता। तो हम उसे स्वदेशी बना देंगे, उसका स्टाइल, डिजाइन और कपड़ा सब भारतीय ढंग से ढाल देंगे।